आरक्षित तिथि 28.04.2022

वितरण तिथि : 28.04.2022

<u>उत्तरखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

रिट याचिका (एम/एस) सं. 861/ 2022

रवींद्र सिंह पनियाला ..... याचिकाकर्ता

- बनाम

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य ..... प्रतिवादीगण

मामले में पेश अधिवक्तागण:

रिट आवेदक के लिएः श्री अरविंद कुमार शुक्ला, श्री वासु चौधरी, श्री तुषार स्वामी और सुश्री नीना शुक्ला - रिट आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण

प्रतिवादीगण के लिएः श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता।

श्री के.एन.जोशी, राज्य/प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता।

<u>कोरमः</u>

<u>श्री संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति</u>

<u>श्री रमेश चंद्र खुल्बे, न्यायमूर्ति</u>

संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति. (प्रति)

1. रिट आवेदन दायर करके, याचिकाकर्ता, जो उत्तराखंड राज्य के २०२२ के उप-चुनाव में 32-खानपुर निर्वाचन क्षेत्र, जिला हरिद्वार के उम्मीदवार हैं, ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

" (ए)- प्रतिवादी संख्या 4 उमेश कुमार शर्मा के संबंध में सभी आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड मंगाने के लिए आवश्यक आदेश/निर्देश पारित करें और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 146 के तहत उचित जांच करने और प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ आगे कार्रवाई करने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश/निर्देश पारित करें।

(बी)- प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को अधिकार-पृच्छा की प्रकृति में रिट, आदेश/निर्देश जारी करें कि प्रतिवादी संख्या 4 को प्रोफार्मा-26 के तहत झूठे शपथ पत्र की घोषणा के सत्यापन के बिना चुनाव लड़ने की अनुमति कैसे दी गई है।

(सी)- भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08-01-2022 में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रतिवादी को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश/निर्देश जारी करें।

(डी)- परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश/दिशा-निर्देश जारी कर प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 राज्य चुनाव आयोग और अन्य सभी जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का आदेश दें, जिन्होंने उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के बारे में सही जानकारी छिपाकर, प्रतिवादी नंबर 4 की उम्मीदवारी की अनुमति प्रदान की है।

(ई)- रिट की प्रकृति में ऐसे अन्य आदेश पारित करें जैसे कि यह माननीय न्यायालय निष्पक्ष चुनावों के लिए पूर्ण अनुपालन के लिए उचित दिशानिर्देश देता है।

(एफ)- रिट की प्रकृति में ऐसा अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय प्राकृतिक न्याय के हित में उचित समझे।

(जी)- रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में करें।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि नामांकन दाखिल करते समय, प्रतिवादी नंबर 4, रिटर्निंग कैंडिडेट ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को प्रतिबिंबित नहीं किया

और इसलिए, चुनाव आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी को अवैध रूप से स्वीकार कर लिया गया है और इसलिए, एक परमादेश की रिट और योग्यता वारंटो की रिट जारी की जानी चाहिए।

3. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने 2014 (14) एससीसी 162 में रिपोर्ट किए गए किसान शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत और अन्य के फैसले का आश्रय लिया और तर्क दिया कि उचित जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के मद्देनजर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33ए (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) का उल्लंघन हुआ है और, इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता ने 2019 की फौजदारी अपील संख्या 1515-1516 में सतीश उके बनाम देवेंद्र गंगाधरराव फड़नवीस और अन्य के मामले का आश्रय लिया, जिसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर, 2019 को किया था। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125-ए के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लेने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य के मामले में, (2015) 3 एससीसी 467 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन क्षेत्र की उचित जानकारी देने की आवश्यकता और उचित जानकारी न देने के परिणामों को दोहराया है।

4. दूसरी ओर, चुनाव आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित सहायरा ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 329 के अनुसार,न्यायालय को इस तरह के आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पहले ही चुनाव याचिका संख्या 06/ 2022 रवींद्र सिंह बनाम उमेश कुमार शर्मा दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुका है, जिसे नियत पीठ द्वारा दिनांक 25.04.2022 को स्वीकार कर लिया गया हैचुनाव आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 इस मामले में लागू नहीं होगी।

5. इस स्तर पर यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 के चुनाव को चुनौती देते हुए एक उचित चुनाव याचिका दायर करके पहले ही इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव याचिका अभी इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।चुनाव याचिका अभी तक इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

6. हमने याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामले की जांच की है और निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया है:

(i) किसन शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र द्वारा तय किए गए चुनाव विवाद से उत्पन्न सिविल अपील के मामले पर विचार कर रहा था। इस प्रकार, हालांकि ये टिप्पणियाँ सूचना के अधिकार के संबंध में हैं, इसके परिणामस्वरूप, इसमें तय किया गया अनुपात वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू नहीं होगा।

(ii) कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तमिलनाडु उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई एक चुनाव याचिका से उत्पन्न विशेष अपील पर विचार कर रहा था।

(iii) कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य (उपरोक्त) का मामला, ऐसा करने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा झूठा हलफनामा दायर करने के संबंध में संज्ञान लेने से संबंधित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि इसे सामने लाया जाता है, तो प्रथम दृष्टया रिटर्निंग कैंडिडेट ने झूठा हलफनामा दायर किया है तो आपराधिक मामला शुरू किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान न लेना उचित नहीं है।

इस प्रकार, यह पाया गया कि उपरोक्त मामलों के तथ्य वर्तमान मामले से अलग हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग को निर्देश देने और प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग कर रहा है।

7. के वेंकटचलम बनाम अवामिकन और एक अन्य बनाम 199 (4) एससीसी के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि रिटर्निंग उम्मीदवार तमिलनाडु निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में निर्वाचक नहीं था। उन्होंने अपने नामांकन पत्र में किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण किया है। उस विशेष मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब संसद या विधान सभा के चुनाव के लिए मतदान या पुनर्मतदान प्रक्रिया चल रही हो, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है और वह पीड़ित पक्षों का उपचार संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) सपठित अधिनियम के तहत है। अधिनियम की धारा 100 और 101 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर धारा 81 के तहत चुनाव याचिका दायर करके चुनाव को चुनौती देने का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता के पास संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड (सी) सपठित आर.पी.एक्ट की धारा 5 के तहत बुनियादी योग्यता का अभाव था, जो अनिवार्य करता है कि किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले व्यक्ति को उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना होगा।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को तमिलनाडु का विधायक होने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। उन्होंने अपने नामांकन प्रपत्र में किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण किया। वह आपराधिक रूप से भी उत्तरदायी होंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं का प्रतिरूपण करते हुए शपथ पत्र पर अपना नामांकन दाखिल किया था।वह जानते थे कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, फिर भी वे बैठे और विधायक के रूप में मतदान किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि वह प्रत्येक उस दिन के संबंध में 500/- रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी है जिस दिन वह बैठता है या मतदान करता है और यह जुर्माना राज्य के ऋण के रूप में वसूल किया जा सकता है। अधिनियम के तहत कोई निर्णय नहीं लिया गया है और संविधान में कोई अन्य प्रावधान नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए जुर्माने को राज्य के ऋण के रूप में कैसे वसूल किया जाना है। फिर भी अपीलकर्ता दंड का भागी है।यदि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें विधानसभा में बैठने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है तो उनका कृत्य संविधान के साथ धोखाधड़ी होगा।अनुच्छेद 226 को यथासंभव व्यापक शर्तों में शामिल किया गया है और जब तक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है, तब तक अनुच्छेद

226 के तहत इसकी शक्तियों का प्रयोग तब किया जा सकता है जब कोई ऐसा कार्य हो जो कानून के किसी भी प्रावधान के खिलाफ हो या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हो और जब इसका सहारा लिया गया हो। उचित राहत के लिए अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता।वर्तमान जैसी परिस्थितियों में अनुच्छेद 329 (बी) की बाधा लागू नहीं होगी जब मामला अनुच्छेद 191 और 193 के अंतर्गत आता है और पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।ऐसा हो सकता है कि अनुच्छेद 192 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि अपीलकर्ता को उसके चुनाव से पहले अयोग्य ठहराया गया था।इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार करने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सही किया और घोषित किया कि अपीलकर्ता एक विधायक के रूप में तमिलनाडु विधान सभा में बैठने का हकदार नहीं था।

8. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त रिपोर्ट किए गए मामले से अलग हैं।यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सं. 4 पर कई आपराधिक मामले लंबित हैं और उन्होंने अपने नामांकन के समय मामलों के बारे में खुलासा नहीं किया है। हालाँकि, इस तथ्य पर चुनाव आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने विवाद किया है, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 4 ने उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामलों को लंबित दर्शाया है, लेकिन अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता संलिप्तता के बारे में आरोप सही नहीं हैं क्योंकि उन मामलों में संज्ञान नहीं लिया गया है या मामलों को दोषमुक्ति दिया गया है। इस संदर्भ में, हम संविधान के अनुच्छेद 329 पर ध्यान देते हैं, जो निम्नलिखित हैः

> "329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी
>
> (ए) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता, जो अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत बनाया गया है या बनाए जाने का इरादा है, किसी भी अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(बी) संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन या किसी भी सदन के चुनाव पर ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत चुनाव याचिका के अलावा कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा और ऐसे तरीके से जैसा कि उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जा सकता है।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को चुनाव मामलों में रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के तहत संसद के सदन या राज्य विधान सभा के सदन के किसी भी चुनाव पर, कानून के तहत प्रदान किए गए प्राधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने के अलावा सवाल नहीं उठाया जाएगा।

9. हालाँकि, पहले उल्लिखित कुछ मामलों में, यदि रिटर्निंग उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने वाली पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति की चुनाव याचिका को बनाए रखने में असमर्थ है, जो प्रतिरूपण आदि का दोषी है, तो एक रिट आवेदन पर विचार किया जा सकता है।हालाँकि, यहाँ यह मामला नहीं है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, और उन मामलों को उसके नामांकन पत्र में प्रतिबिंबित नहीं किया गया है, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है।

10. यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिस पर चुनाव याचिका में विचार किया जा सकता है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पहले ही दायर किया जा चुका है। इस स्तर पर यह भी विवाद में नहीं है कि वैकल्पिक और प्रभावकारी उपाय की उपलब्धता के मामले में, रिट आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।इसके अलावा, जहां प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कथित आपराधिक मामले लंबित हैं, वह तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्णय सबसे प्रभावी ढंग से एक चुनाव याचिका में किया जा सकता है। मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्यों पर गौर करना होगा। ऐसे तथ्यों को प्रभावी ढंग से रिट आवेदन में शामिल नहीं किया जा सकता है।न्यायालयों को हमेशा समानांतर कार्यवाही से बचना चाहिए।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता एक चुनाव याचिका रख सकता है और उसने चुनाव याचिका

संख्या ०6/ 2022 दायर की है, जो निर्धारित पीठ के समक्ष लंबित है, और 25.04.2022 को स्वीकार कर ली गई है।इस प्रकार, चुनाव याचिका दायर करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ लगाए गए तथ्यात्मक आरोप से, प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध रिट कोर्ट की ओर से परमादेश की रिट जारी करना या अधिकार पृच्छा की रिट जारी करना उचित नहीं होगा। निर्वाचन आयोग के पास कदाचार के किसी भी आरोप से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने का क्षेत्राधिकार है।ऐसी शक्ति इसमें निहित है और न्यायालय को हर मामले में चुनाव आयोग को जांच करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित नहीं करना चाहिए।

11. चुनाव आयोग की शक्तियाँ अधिनियम, विशेष रूप से, इसकी धारा 146 में निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार है:

"146 - निर्वाचन आयोग की शक्तिया:-

(1) जहां अनुच्छेद 103 के तहत या, जैसा भी मामला हो, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 14 की उपधारा (4) के तहत राष्ट्रपति को कोई राय देने के संबंध में) , या अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल को, चुनाव आयोग जांच करना आवश्यक या उचित समझता है, और आयोग इस बात से संतुष्ट है कि संबंधित पक्षों द्वारा अपनी मर्जी से दायर किए गए हलफनामों और ऐसी जांच में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यदि वह उस मामले पर निर्णायक राय नहीं दे सकता है जिसकी जांच की जा रही है, तो ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए, आयोग के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां (5/1908) होंगी, अर्थात्:

(ए) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जांच करना;

(बी) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु की खोज और प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता;

(सी) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(डी) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(इ) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना;

12. संविधान का अनुच्छेद 192 सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न के निर्णय के संबंध में प्रावधान करता है, जो इस प्रकार है:

"192. सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय

(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को निर्णय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

13. इसी तरह, संविधान की खंड 103, संसद के सदन के सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान करती है, जो इस प्रकार हैः

"103.सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय

(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।

14. इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192 सपठित धारा 146 को पढ़ने से पता चलता है कि यदि संसद या विधान सभा का कोई भी सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, को निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। संविधान के अनुच्छेद 102 की उप-धारा (बी) में प्रावधान है कि ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति/राज्यपाल चुनाव आयोग का मत प्राप्त करेंगे और इसी मत के अनुसार कार्य करेंगे।इस प्रकार, अधिनियम की धारा 146 तभी लागू होती है जब विधान सभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति या राज्यपाल से संदर्भ प्राप्त होता है। इसे इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में लागू करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

15. अधिनियम की धारा 125ए के अनुसार झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर जुर्माने की कार्यवाही इस प्रकार है:

"[125ए। गलत शपथ पत्र आदि दाखिल करने के लिए जुर्माना।

एक उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से चुनाव में निर्वाचित होने के इरादे से,

(i) धारा 33ए की उपधारा (1) से संबंधित जानकारी देने में विफल रहता है; या

(ii) गलत जानकारी देगा जिसके बारे में वह जानता है या जिसके गलत होने पर विश्वास करने का उसके पास कारण है; या

(iii) किसी भी जानकारी को छुपाता है,

धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए उनके नामांकन पत्र में या उनके हलफनामे में, जो धारा 33 ए की उप-धारा (2) के तहत दिया जाना आवश्यक है, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, फिलहाल लागू होने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।]"

16. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए नामांकन पत्र में दायर "फॉर्म 26" या शपथ पत्र में मिथ्याता के ऐसे आरोप का सवाल है, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के लिए अधिनियम की धारा 125 ए के तहत कानूनी उपाय उपलब्ध है। इसलिए, उचित कानूनी उपाय की मांग किए बिना रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है।इसके अलावा, किसान शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रय स्वांत और अन्य (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कोई भी हलफनामे में गलत बयान दे सकता है और यदि रिटर्निंग उम्मीदवार गैर-प्रकटीकरण का दोषी पाया जाता है, शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी होने से रिटर्निंग उम्मीदवार के नामांकन को अनुचित घोषित किया जा सकता है आदि ऐसी प्रक्रिया चुनाव याचिका में उपलब्ध है।

17. कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि हलफनामे में भौतिक जानकारी को छिपाना "अनुचित प्रभाव" के भ्रष्ट आचरण के समान है और केवल उच्च न्यायालय ही चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है। और, इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी संख्या 4 के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध उपाय को ध्यान में रखते हुए; और वह पहले ही उस उपाय का प्रयोग कर चुका है और वह इस न्यायालय की नियत पीठ के समक्ष लंबित है। एक ही तथ्यात्मक पहलू पर रिट आवेदन का विचरण , एक अलग प्रतीत होने वाली प्रार्थना के साथ एक चुनाव याचिका, वास्तव में, एक समानांतर कार्यवाही होगी।एक ही उद्देश्य के लिए समानांतर और एकाधिक कार्यवाहियों का ऐसा विचरण सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा।

18. मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि यह रिट आवेदन विचारणीय नहीं है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।हालाँकि, वर्तमान रिट आवेदन में की गई किसी भी टिप्पणी का इस न्यायालय की किसी अन्य पीठ के समक्ष लंबित चुनाव याचिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कोई लागत नहीं।

(रमेश चन्द्र खुल्बे, न्यायमूर्ति) (एस.के.मिश्रा, न्यायमूर्ति)

(नियमानुसार इस आदेश की प्रति तत्काल उपलब्ध करायें)